राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........ 9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापुर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार , 13 मार्च 2026

वर्ष 14, अंक 320, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

रसोई गैस की किल्लत, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें..03

छात्रवृत्ति और टैबलेट की मांग को लेकर बलिया में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी..04

DU में प्रोटेस्ट पर बैन को लेकर हाई कोर्ट सख्त, पूछा-पूरी तरह रोक कैसे लगा सकते हैं?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) और दिल्ली पुलिस के उन ऑर्डर पर सवाल उठाए, जिनमें यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और जुलूस पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर कानून-व्यवस्था का कोई उल्लंघन होता है, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं हो सकता. चीफ जस्टिस उपाध्याय ने पूछा कि 'हमारी साफ राय है कि पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता. ऑर्डर देखें. पब्लिक मीटिंग, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, विरोध, धरना या किसी भी तरह का आंदोलन. तो, आप (DU) अपनी सख्ती में, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, रैली और जुलूस को भी अपने दायरे में ले लेंगे. आप इसे कहां तक सही ठहरा सकते हैं? आपको यह ऑर्डर पास करने की क्या ज़रूरत थी? अगर किसी ने (धारा) 144 (CrPC) का उल्लंघन किया था, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था. आपने यह ऑर्डर क्यों जारी किया? कृपया मुझे बताएं कि आपको यह ऑर्डर जारी करने की क्या जरूरत थी?' कोर्ट ने पुलिस के प्रोटेस्ट पर रोक लगाने का ऑर्डर पास करने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के सेक्शन 144 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया।

कोर्ट ने DU से एक हफ्ते में मांगा जवाब

हालांकि, कोर्ट ने DU और पुलिस के निर्देशों पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया. इसके बजाय, कोर्ट ने पुलिस और ष्ठ को एक हफ्ते के अंदर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि वह मामले पर फैसला करेगी. कोर्ट ने छात्रों के बर्ताव पर भी सवाल उठाया, यह बताते हुए कि वह इस मामले पर सिर्फ इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि यह आर्टिकल 19 (बोलने और बोलने की आजादी) के अधिकारों से जुड़ा है. इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सिर्फ आर्टिकल 19 की वजह से हम इस मामले में दखल दे रहे हैं. आपको (स्टूडेंट्स) ठीक से पेश आना चाहिए. ऐसी हालत क्यों हुई? प्रॉक्टर (DU के जिन्होंने रोक के आदेश जारी किए) भी एक एकेडमिक हैं. वह ऐसा आदेश क्यों देंगे? कोई भी एकेडमिशियन ऐसा आदेश नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह से आप पेश आ रहे हैं. कोर्ट ने कहा, 'देखिए (दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन) चुनावों के दौरान क्या हुआ था।

'25 मार्च को होगी अगली सुनवाई

आखिरकार, बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश DU के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट उदय भदौरिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. भदौरिया ने प्रॉक्टर ऑफिस के 17 फरवरी के एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस और उससे जुड़े कॉलेजों में पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के शांतिपूर्ण जमावड़े पर रोक लगाई गई है. यह फैसला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों के बाद लिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन पर लगाई थी रोक

इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज की तरफ से जारी एडवाइजरी में रोक को और मजबूत किया गया, जिसमें सस्पेंशन और नौकरी से निकालने जैसी डिसिप्लिनरी कार्रवाई की चेतावनी दी गई. कॉलेजों ने स्टूडेंट्स और स्टाफ को सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा कंटेंट शेयर करने से भी सावधान किया. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने भी विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ रोक के आदेश जारी किए. दिल्ली पुलिस के वकील के आज दिए गए बयान के मुताबिक, रोक को अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पूरी तरह से रोक संविधान के आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करती है. यह कहा गया कि यह आदेश असंगत है और एकेडमिक बातचीत पर बुरा असर डालता है।

केरल HC से नहीं मिली राहत, CPI-M कार्यकर्ता मर्डर केस में BJP के 5 सदस्यों की उम्रकैद बरकरार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

केरल हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में साल 2006 में कन्नूर में एक युवा CPI(M) कार्यकर्ता पर बम फेंककर हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 5 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कन्नूर जिले में 2 दलों के बीच राजनीतिक दुश्मनी की वजह से एक शख्स की जान जाने की एक और घटना करार दिया।

अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जोबिन सेबेस्टियन की बेंच ने कहा कि 24 साल के याकूब की सिर पर बम फेंककर हत्या, घटना से कुछ दिन पहले BJP के एक कार्यकर्ता पर हुए हमले का बदला था।

2 राजनीतिक दलों की दुश्मनी

बेंच ने कहा, 'कन्नूर जिले में 2 राजनीतिक दलों, CPI(M) और BJP के बीच राजनीतिक दुश्मनी की वजह से यह हत्या हुई. इस बार इस दुश्मनी में 24 साल के युवक की जान चली गई.' हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें प्रकाशन (48), विजेश (43), मनोहरन (31) काव्येश (43) और शंकरन मास्टर (49) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों और मृतक की पार्टी के अन्य साथियों के बयानों में कोई अंतर नहीं था, जिन्होंने हमले का सामना किया और पांचों आरोपियों को मुख्य अपराधी बताया था. हाई कोर्ट ने कहा, 'डॉक्टर के सबूतों और उनके द्वारा जारी किए गए पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट को मिलाकर पढ़ने से बेशक यह पता चलता है कि याकूब की मौत हत्या थी और सिर पर लगी चोट बम धमाके की वजह से हुई थी.

FIR में देरी की याचिका ठुकराई

साथ ही यह भी कहा कि हत्याकांड के 2 गवाहों को 13 जून, 2006 की रात को BJP कार्यकर्ताओं द्वारा CPI(M) कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले में चोटें आई थीं, और हमले के बारे में उनका बयान उनके शरीर पर मिले घावों के नेचर से बहुत मेल खाता है. बेंच ने 2 गवाहों की यह बात भी स्वीकार कर ली कि उन्होंने एक आरोपी को पीड़ित के सिर की ओर से बम फेंकते देखा, जो फट गया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई।

बचाव पक्ष के वकीलों ने सुनवाई के दौरान यह दावा किया था कि गवाहों के बयान एक जैसे नहीं पाए गए और उनमें अंतर था, लेकिन बेंच ने इसे खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने स्नढ्ढक्र दर्ज करने में देरी की बचाव पक्ष की दलील को भी खारिज कर दिया. दावा किया गया कि पुलिस शुरू में इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग पर लगी थी जिससे इस तरह की दूसरी घटना घटने न पाए, और पीड़ित की मौत के करीब 6 घंटे बाद केस दर्ज किया गया. बेंच ने यह भी माना कि भले ही बम एक आरोपी ने फेंका था, लेकिन वे सभी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह काम याकूब को मारने के लिए गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के एक ही मकसद को पूरा करने के लिए किया गया था. आरोपी जिसने देसी बम फेंककर और धमाका करके याकूब के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई, उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि इस मामले में हत्या करने का कोई इरादा नहीं था.' बेंच ने पांचों आरोपियों की अपील को उनकी सजा और उम्रकैद की सजा के खिलाफ खारिज कर दिया।

संक्षिप्त ख़बरें

'प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने जा रहा, मुझे ढूंढना मत'... इंदौर में घर से भागा 16 साल का छात्र

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के प्रति भक्तों की दीवानगी चरम पर है. उनकी एक झलक पाने के लिए प्रतिदिन देर रात हजारों लोग सड़क पर डेरा डालते हैं. गंभीर किडनी की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उनका सादगी भरा जीवन, रात 2:20 बजे की पदयात्रा और राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम ही लोगों को आकर्षित करता है. यही वजह है कि भक्त उनके आश्रम 'केली कुंज' पर भारी संख्या में पहुंचते हैं. कई भक्त तो ऐसे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचते हैं, जो उनके प्रति समर्पण को दर्शाता है।

प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने निकला छात्र

हालांकि कई भक्त इसी भक्ती में नादानी कर बैठते हैं, जिससे उनके परिवार वाले काफी परेशान हो जाते हैं. मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है. खजराना थाना क्षेत्र का रहने वाला एक 16 वर्षीय छात्र प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने के लिए वृंदावन के लिए निकल पड़ा, वो भी घर में बिना किसी को बताए. घरवालों को इसकी जानकारी तब हुई, जो उन्होंने छात्र का लिखा लेटर पढ़ा. लेटर में छात्र ने लिखा था कि, मैं प्रेमानंद जी महाराज का शिष्य बनने जा रहा हूं. मुझे तलाश मत करना।

थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

छात्र का लेटर पढ़ घरवाले परेशान हो गए. उन्होंने आनन-फानन में इसकी जानकारी खजराना थाना पुलिस को दी. पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी छात्र घर से क्रिकेट खेलने की बात कहकर निकला था, लेकिन घर पर नहीं लौटा. जब काफी देर तक नहीं लौटा तो घरवालों को चिंता हुई. इस पर उन्होंने छात्र को आसपास तलाशना शुरू किया, लेकिन छात्र नहीं मिला. परिजनों ने खजराना थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

मां के पास रखे 1000 रुपए लेकर गया

पुलिस ने बताया कि छात्र के घर पर एक लेटर भी मिला, जिसमें उसने प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने का जिक्र किया है. वह अपनी मां के पास रखे हुए 1000 भी लेकर गया है और कहा है कि मेरे दोस्त से ले लेना. वह आपको दे देगा. बच्चा काफी छोटा है, जिस कारण परिवार काफी चिंतित है. पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है. एक टीम वृंदावन भी गई है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी बच्चे की तस्वीर शेयर की गई है, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द तलाशा जा सके।

घर में नमाज अदा करने से रोकने के मामले में बरेली के डीएम-एसएसपी इलाहाबाद HC में तलब, 23 मार्च को हाजिर होने का आदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने घर में नमाज अदा करने से रोके जाने के मामले में बरेली के जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्या को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वे उपस्थित नहीं होते तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

हाई कोर्ट का हसीन खान की याचिका पर आदेश

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मकान मालिक को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने तारिक खान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

फैसला आने तक 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहेंगे गार्ड

कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक हसीन खान की सुरक्षा के लिए दो हथियारबंद गार्ड तैनात किए जाएं जो इस मामले में फैसला आने तक 24 घंटे हर समय तैनात रहेंगे। हसीन खान के शरीर अथवा उनकी संपत्ति के खिलाफ यदि कोई हिंसा की जाती है तो यह प्रथम दृष्टया राज्य की शह पर मानी जाएगी।

पिछली सुनवाई पर अवमानना नोटिस जारी की थी

कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर बरेली के डीएम और एसएसपी को पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया था। बरेली निवासी तारिक खान ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 16 जनवरी को स्थानीय अधिकारियों ने निजी आवास के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं है।

घर के मालिक का दर्ज हुआ बयान

बुधवार को डीएम व एसएसपी की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई। साथ ही कोर्ट में घर के मालिक हसीन खान का बयान दर्ज किया गया। मकान मालिक ने कोर्ट को बताया कि वह अपने घर में परिवार के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तभी पुलिस उठा ले गई। आरिफ प्रधान और मुख्तयार ने धमकाया कि यदि उसने कोर्ट में सच बोला तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। उसे जबरन गांव के बाहर ले जाकर पुलिस की मौजूदगी में सादे कागजों पर अंगूठा लगवाया गया।

धनबाद में पटना से आ रही बस में खाद्य विभाग ने मारा छापा, 1400 KG नकली पनीर और 90 KG नकली घी बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने पटना से बोकारो जा रही बुंदेला बस से भारी मात्रा में नकली पनीर, धी व आदि जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने गुरुवार तड़के तीन बजे बस स्टैंड पर मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बिहार से आने वाली बुंदेला बस से 1400 किलो नकली पनीर तथा 90 किलो नकली घी बरामद किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहार (पटना) से बोकारो आने वाली बुंदेला नाम की बस, बीआर 21 पी 3632, से 1400 किलो नकली पनीर एवं 90 किलो नकली घी (6 टीन) और अन्य खाद्य सामग्रियां जब्त की।

साथ ही बुंदेला बस के ड्राइवर एवं खलासी और बस को धनबाद थाना को सौंप दिया। इसके अलावा बिहार से आने वाली सभी बसों में सघन जांच अभियान जारी रहा। उन्होंने बताया कि सभी पनीर पटना से धनबाद जिले में लगन के समय एवं त्योहारों के अवसर पर खपाने के लिए लाया जा रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में धनबाद में पहली बार मिलावटी पनीर का पकड़ा गया है। मिलावटखोरों के विरुद्ध ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा।

जुलाई 2025 में भी बुंदेला बस मिला था भारी मात्रा में पनीर

यह पहली बार नहीं है जब बुंदेला बस का नाम आया है। जुलाई 2025 में भी इसी बस से फूड सेफ्टी विभाग ने 900 किलो मिलावटी पनीर, लड्डू आदि जब्त किया था। तब उस खेप को धनबाद के नामी होटलों और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जाना था। बार-बार एक ही बस का नाम आने से अब परिवहन विभाग और पुलिस भी सतर्क हो गई है।

यमुना बेवरेजेज धोखाधड़ी मामला, सिरमौर से बकाया भुगतान और कंपनी के दस्तावेज लेकर भागा आरोपी; FIR दर्ज

नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के पुरुवाला पुलिस थाना में यूपी की एक कंपनी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार आरोपी कंपनी मालिक नकदी, कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और वाहन लेकर फरार हो गया। पांवटा साहिब के नारीवाला स्थित यमुना बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के लेखाकार मोहित कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी कंपनी केएम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन नामक कंपनी मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और कच्चा माल सप्लाई करती थी। उक्त कंपनी के मालिक कावेश मल्होत्रा निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हैं। शिकायत में बताया गया है कि उनकी कंपनी द्वारा केएम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को कुल 4 करोड़ 33 लाख 81 हजार 569 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि बदले में कंपनी की ओर से 3 करोड़ 66 लाख 93 हजार 114 रुपए की सप्लाई दी गई। इस प्रकार 66 लाख 88 हजार 455 रुपए की राशि शेष रह गई।आरोप है कि 1 मार्च 2026 को कावेश मल्होत्रा अपने साथी ललित कुमार श्रीवास्तव निवासी बरेली उत्तर प्रदेश के साथ दो लाख रुपए नकद, कंपनी के महत्वपूर्ण कागजात और कंपनी की गाड़ी नंबर HP17G-1408 लेकर फरार हो गया।

इंद्रपुरी सड़क विवाद में आप-भाजपा आमने-सामने, विधायक उमंग बजाज पर हमले का आरोप; भाजपा ने कहा- आप पार्षद ने की मारपीट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिमी दिल्ली। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी में सड़क निर्माण के दौरान शुरू हुआ विवाद अब थाने की चौखट तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस पूरे प्रकरण में एक-दूसरे पर मारपीट, अभद्रता और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए हैं।

आप का आरोप, विधायक की मौजूदगी में हुआ हमला

राज्यसभा सांसद और आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमंग बजाज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुधवार रात इंद्रपुरी वार्ड में पार्षद ज्योति गौतम के क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। पार्षद ज्योति गौतम और शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष संजय बैरवा जब वहां निरीक्षण करने पहुंचे, तो विधायक उमंग बजाज ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर हमला करवाया। विधायक की मौजूदगी में उनके गुंडों ने संजय बैरवा की पिटाई की और महिला पार्षद के साथ गाली-गलौज व अभद्रता की। संजय सिंह ने नाराजगी जताई कि पुलिस में शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

विधायक उमंग बजाज ने किया पलटवार

भाजपा विधायक उमंग बजाज ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि इंद्रपुरी सी ब्लाक में सड़क पिछले ढाई साल से खराब थी, जिसे निगम पार्षद और पूर्व विधायक ने फंड होने के बावजूद नहीं बनवाया। स्थानीय लोगों के आग्रह पर उन्होंने खुद इसे शुरू करवाया। जब काम चल रहा था तब ज्योति गौतम और संजय बैरवा वहां आए और भाजपा कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहे। मारपीट की। उन्होंने एक दिव्यांग कार्यकर्ता का भी उपहास उड़ाया। मारपीट व कहासुनी के दौरान संजय बैरवा एक इमारत के बाहरी हिस्से से टकराकर संतुलन खो बैठे और गिर गए, जिन्हें बचाने के चक्कर में पार्षद ज्योति गौतम भी गिर पड़ीं। विधायक ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

पूर्व विधायक सोमेश शौकीन को 10 करोड़ की रंगदारी की धमकी

आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मटियाला के पूर्व विधायक सोमेश शौकीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब पूर्व विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। सोमेश शौकीन से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हैरानी की बात है कि पुलिस आयुक्त उन्हें मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। सांसद ने कहा दिल्ली में गिरती कानून व्यवस्था का मामला वे राज्य सभा में उठाएंगे।

विकास कार्यों का श्रेय लेना चाहती हैं आप पार्षद

दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2024 में राजेंद्र नगर के तत्कालीन आप विधायक ने दिल्ली जल बोर्ड के फंड से कुछ विकास कार्य शुरू करवाने के लिए इंद्रपुरी वार्ड में सड़क की खोदाई तो करा दी लेकिन वहां ना विकास कार्य हुआ ना सड़क ही बनी। इस वर्ष फरवरी में सांसद बांसुरी स्वराज एवं विधायक उमंग बजाज ने प्रयास कर यहां विकास कार्य पूरा करवाया। पार्षद ज्योति गौतम अब निगम चुनाव नजदीक देखकर केवल काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 41 साल पुरानी एमसी मेहता याचिका बंद, एनसीआर में प्रदूषण की सुनवाई का बदल गया तरीका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। वर्ष 1985 में पर्यावरणविद एमसी मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें एनसीआर में व्याप्त वायु प्रदूषण की समस्या को उजागर किया गया था। दशकों से कोर्ट इसी याचिका के नाम पर कई नए-नए मुद्दों पर सुनवाई कर रहा था। इसी याचिका के तहत आयु पूरी कर चुके वाहनों का मामला, सीएनजी, पटाखे बंदी आदि कई बड़े मसलों पर कोर्ट सुनवाई करती रही है। मगर अब एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाली मूल याचिका को कोर्ट ने गुरुवार को निस्तारित करते हुए इसे पुनः नामित (re-captioned) करने का आदेश दिया है।

स्वत: संज्ञान के रूप में किया पुनः नामित

बता दें कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाली याचिका में टैग करके दिल्ली में व्याप्त वायु प्रदूषण सहित कई याचिकाओं को दशकों से सुनवाई की जा रही थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तकरीबन 41 साल पुरानी मूल याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि कार्यवाही को स्वतः संज्ञान के रूप में पुनः नामित किया जाए, जिसका शीर्षक होगा 'एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर पुनर्विचार' (ReÑ Issues of Air Pollution in the National Capital Region)।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'इस याचिका में अदालत ने एनसीआर में बह रही जहरीली वायु को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निरंतर परमादेश (mandamus) के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं।' कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा वर्ष 1985 में उठाया गया था, लेकिन 1990 के दशक में इसमें तेजी आई, जिसमें नए मानक लागू किए गए और वाहनों की आयु सीमा तय करने तथा अन्य कई जरूरी उपाय किए गए।

मूल रिट याचिका क्यों की गई पुनः नामित?

निर्देश में आगे कहा गया कि अधिकांश मामलों में समय-समय पर अदालत द्वारा सुनवाई कर आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। पक्षकारों की सुनवाई के बाद अब यह उचित समय है कि 1985 की मूल रिट याचिका से उत्पन्न कार्यवाही का निस्तारण किया जाए। यह सुझाव दिया गया कि 1985 में सामने लाया गया यह मुद्दा हाल का नहीं है, इसलिए याचिका को उचित रूप से पुनः नामित किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विद्वान एमिकस क्यूरी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम औपचारिक रूप से डब्ल्यूपी (सिविल) 1985 का निपटारा करते हैं। उन प्रस्तावों का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने भी समर्थन किया है।

रजिस्ट्री को दिया गया आदेश

पीठ के आदेशानुसार, अब रजिस्ट्री द्वारा उस मामले में कोई आईए (इंटरलॉक्यूट्री एप्लीकेशन) या एमए (मिसलेनियस एप्लीकेशन) दर्ज नहीं की जाएगी। इसी के साथ पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि स्वतः संज्ञान (suo motu) कार्यवाही 'एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर' के शीर्षक से पंजीकृत किए जाएं। वर्तमान में लंबित सभी आईए को रिट याचिकाओं के रूप में पुनः दुरुस्त किया जाए और प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से निस्तारित किया जाए।

अमेरिका-इज़रायल-ईरान युद्ध, मुज्तबा ख़ामेनेई के नेतृत्व के भविष्य की अग्निपरीक्षा

मध्य-पूर्व की राजनीति एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी दिखाई दे रही है। वर्षों से सुलग रही अमेरिका-इज़रायल और ईरान की प्रतिद्वंद्विता अब खुलकर युद्ध में बदल चुकी है। यह केवल तीन देशों के बीच संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा राजनीति और धार्मिक-राजनीतिक ध्रुवीकरण का ऐसा जटिल समीकरण है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस युद्ध का सबसे नाटकीय और निर्णायक मोड़ यह रहा जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खेमनई की हत्या कर दी गई और उसके बाद ईरान ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुज्तबा खेमनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। यह घटना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला देने वाली घटना थी। एक तरफ अमेरिका और इज़रायल इस युद्ध को ईरान की सैन्य और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता और इस्लामी व्यवस्था पर हमला मान रहा है।

ईरान और इज़रायल के बीच तनाव पिछले कई दशकों से बना हुआ है। ईरान खुले तौर पर इज़रायल की नीतियों का विरोध करता रहा है और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसका रुख बेहद आक्रामक रहा है। दूसरी ओर इज़रायल को यह भय लंबे समय से लगता रहा है कि यदि ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो वह उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

अमेरिका भी लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कूटअमेरिका-इज़रायल-ईरान युद्ध, मुज्तबा ख़ामेनेई के नेतृत्व के भविष्य की अग्निपरीक्षा।नीतिक दबाव डालता रहा है। विशेष रूप से जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राजनीति में प्रभावी हुए, ईरान के प्रति अमेरिकी नीति और कठोर हो गई। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी ईरान के परमाणु समझौते को समाप्त किया और अब युद्ध की स्थिति में भी उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है।इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं और अमेरिका की रणनीतिक नीति के मेल ने इस संघर्ष को और तीखा बना दिया। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इज़रायल लंबे समय से ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए किसी बड़े अभियान की तलाश में था और अब उसे अमेरिका का खुला समर्थन मिल गया है।

वैसे वैश्विक राजनीति में यह माना जाता रहा है की ईरान की राजनीति में सर्वोच्च नेता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह केवल धार्मिक प्रमुख ही नहीं बल्कि देश की सैन्य और रणनीतिक नीतियों का अंतिम निर्णयकर्ता भी होता है। ऐसे में जब अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या हुई तो यह ईरान के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका था।

लेकिन सत्ता संरचना ने तेजी से निर्णय लेते हुए उनके पुत्र मुज्तबा ख़ामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। मुज्तबा पहले से ही सत्ता के गलियारों में प्रभावशाली माने जाते थे। वे ईरान की धार्मिक व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से गहरे जुड़े रहे हैं। उनके सत्ता संभालते ही ईरान के तेवर और भी सख्त हो गए। ईरान ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। मिसाइल हमले, ड्रोन अभियान और क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से जवाबी कार्रवाई तेज कर दी गई।

इस संघर्ष की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में फैलता दिखाई दे रहा है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे लगातार खतरे में हैं। ईरान ने अपने समर्थक संगठनों और मित्र देशों के माध्यम से कई अमेरिकी और पश्चिमी ठिकानों पर हमले किए हैं।मध्य-पूर्व के कई देश इस युद्ध से सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेल के समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ गया है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। यदि यह युद्ध लंबा चला तो विश्व अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष को लेकर बेहद कठोर बयान दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यदि ईरान ने अपनी सैन्य नीति नहीं बदली तो उसके नए नेता को भी निशाना बनाया जा सकता है।

ऐसे बयान युद्ध को और अधिक खतरनाक बना देते हैं, क्योंकि जब किसी देश के सर्वोच्च नेता को खुले तौर पर लक्ष्य घोषित किया जाता है तो कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। इससे संघर्ष और भी उग्र हो सकता है।अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुज्तबा ख़ामेनेई का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उनका भविष्य कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगा।

पहला, ईरान की आंतरिक राजनीति। यदि देश के भीतर धार्मिक नेतृत्व, सैन्य प्रतिष्ठान और जनता का समर्थन उन्हें मिलता रहता है तो वे लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकते हैं।

दूसरा, युद्ध का परिणाम ,यदि ईरान इस युद्ध में मजबूत प्रतिरोध दिखाता है तो मुज्तबा ख़ामेनेई एक शक्तिशाली युद्धकालीन नेता के रूप में उभर सकते हैं। इससे उनकी वैधता और प्रभाव बढ़ेगा।उन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है। यदि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव को लगातार बढ़ाते हैं तो यह ईरानी शासन के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।इस युद्ध का असर केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। रूस, चीन और यूरोपीय देशों की प्रतिक्रियाएँ भी इस संघर्ष की दिशा तय कर सकती हैं। यदि बड़ी शक्तियाँ अलग-अलग पक्षों में खुलकर उतर आती हैं तो यह संघर्ष एक बड़े वैश्विक टकराव का रूप ले सकता है। इसके अलावा तेल की कीमतों में उछाल, व्यापार मार्गों पर खतरा और वैश्विक सुरक्षा चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं। दुनिया पहले ही कई आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रही है, ऐसे में यह युद्ध वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा सकता है।

अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि शक्ति, विचारधारा और भू-राजनीतिक हितों की टकराहट है। अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या ने इस संघर्ष को और अधिक उग्र बना दिया है, जबकि मुज्तबा ख़ामेनेई का उदय ईरान की नई राजनीतिक दिशा का संकेत देता है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह युद्ध किस दिशा में जाएगा। क्या यह कूटनीति के जरिए थमेगा या फिर एक व्यापक क्षेत्रीय अथवा वैश्विक युद्ध का रूप ले लेगा? इतना निश्चित है कि मुज्तबा ख़ामेनेई का नेतृत्व इस समय एक कठिन अग्निपरीक्षा से गुजर रहा है। आने वाले समय में वही तय करेगा कि वे ईरान के इतिहास में एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में याद किए जाएंगे या फिर विश्व राजनीति की उथल-पुथल में उनका अध्याय भी एक अस्थिर दौर की कहानी बनकर रह जाएगा।

संजीव ठाकुर

संपादकीय

युद्ध और पर्यावरण विनाशः क्या तय होगी युद्ध थोपने वाले नेताओं की जवाबदेही?

वर्तमान सदी में युद्ध केवल सीमाओं को बदलने या सत्ता परिवर्तन के लिए ही नहीं, बल्कि संसाधनों पर कब्जे, हथियारों के प्रदर्शन और उनके परीक्षण के लिए भी लड़े जा रहे हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि ये युद्ध न केवल मानव सभ्यता को पीछे धकेल रहे हैं, बल्कि पृथ्वी के पर्यावरण पर भी गहरे और दीर्घकालिक घाव छोड़ रहे हैं।

युद्ध के दौरान फटने वाले बम, मिसाइलें और रासायनिक हथियार तेल भंडारों को राख कर रहे हैं, शहरों और जंगलों की हरियाली निगल रहे हैं, जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं और हवाओं को विषैला बना रहे हैं। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है और जैव विविधता पर गहरा संकट मंडरा रहा है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ?युद्ध केवल भूमि और आकाश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनका सबसे मूक और गहरा प्रभाव समुद्रों पर पड़ता है। नौसैनिक युद्धों के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाले युद्धपोत और तेल टैंकरों से होने वाला 'ऑयल स्पिल' (तेल रिसाव) समुद्री जीवों के लिए मौत का वारंट बन जाता है। मिसाइल परीक्षणों और पनडुब्बियों द्वारा छोड़े गए मलबे से समुद्र के तल में भारी धातुएं जमा हो जाती हैं, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अंततः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, आधुनिक युद्धों में उपयोग होने वाले शक्तिशाली सोनार सिस्टम समुद्री स्तनधारियों, जैसे व्हेल और डॉल्फिन की संचार क्षमता और दिशा-ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। लाल सागर और फारस की खाड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वर्तमान सैन्य हलचल वहां के कोरल रीफ (मूंगा चट्टानों) को भी अपूरणीय क्षति पहुँचा रही है, जो हजारों प्रजातियों का घर हैं।

ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब युद्ध पर्यावरण के इतने बड़े विनाश का कारण बनते हैं, तो क्या इन्हें शुरू करने वाले नेताओं और शक्तियों की पर्यावरणीय जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए?

वर्तमान में पश्चिम एशिया का तनाव इस प्रश्न को और अधिक गंभीर बना रहा है। अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच छिड़ा संघर्ष अब भीषण रूप ले चुका है। दोनों ओर से घातक मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात हो रही है। ऐसा ही भयावह मंजर रूस-यूक्रेन युद्ध में भी देखने को मिल रहा है। इन युद्धों का प्रभाव केवल युद्धरत देशों तक सीमित नहीं है। तेल भंडारों, सैन्य ठिकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमलों से निकलने वाला विषैला धुआं, रासायनिक गैसें और सूक्ष्म कण वैश्विक वायुमंडल में घुल रहे हैं। विकसित शहर मलबे के ढेर में बदल रहे हैं, जिससे जल, वायु, पृथ्वी और आकाश प्रदूषित होकर जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध और पर्यावरण विनाश का चोली-दामन का साथ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों ने न केवल लाखों जानें लीं, बल्कि दशकों तक रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाया, जिसने मिट्टी और जल को ज़हरीला बना दिया। खाड़ी युद्ध (1991) के दौरान कुवैत के तेल कुओं में लगाई गई आग आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक है, जिससे महीनों तक लाखों टन कार्बन वायुमंडल में पहुंचा।

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और विशेष रूप से 1999 का कारगिल युद्ध हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए बड़ी चुनौती बना। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य कचरे और विस्फोटों ने संवेदनशील ग्लेशियरों को प्रभावित किया। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए 'एजेंट ऑरेंज' जैसे रसायनों ने लाखों हेक्टेयर वनों को बंजर बना दिया। वहीं, अफगानिस्तान में लगभग दो दशकों तक चली बमबारी ने भूमिगत जल और कृषि योग्य भूमि को भारी क्षति पहुँचाई। एक कड़वा सच यह भी है कि युद्ध न होने की स्थिति में भी सैन्य गतिविधियां प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं। लड़ाकू विमान, टैंक, युद्धपोत और निरंतर होने वाले मिसाइल परीक्षण भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की खपत करते हैं। यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन की समस्या को और विकराल बना रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनईपी जैसे संस्थान युद्ध के दौरान पर्यावरण संरक्षण की वकालत करते रहे हैं, लेकिन आज तक शायद ही किसी वैश्विक नेता को पर्यावरणीय विनाश के लिए दंडित किया गया हो। इन परिस्थितियों में 'इकोसाइड' को अंतरराष्ट्रीय अपराध घोषित करने की मांग की जाना चाहिए । यदि यह अवधारणा कानूनी रूप लेती है, तो भविष्य में पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचाने वाले नेताओं को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि युद्ध केवल मनुष्यों के विरुद्ध हिंसा नहीं, बल्कि प्रकृति के विरुद्ध भी अपराध है। प्रदूषित हवा और ज़हरीली नदियाँ सीमाओं के नक्शे नहीं पहचानतीं; इनका खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। आज वैश्विक राजनीति में 'युद्ध की संस्कृति' को त्यागकर शांति, कूटनीति और 'पर्यावरणीय जिम्मेदारी' को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अन्यथा युद्ध की आग में केवल शहर ही नहीं जलेंगे, बल्कि पृथ्वी का अस्तित्व भी समाप्त होने की संभावना है।

सरेंडर की मांग से भड़का संघर्ष- क्या यह युद्ध लंबा और विनाशकारी होगा?

[मध्य पूर्व में बढ़ती जंगः तेल संकट और परमाणु खतरे से कांपी दुनिया]

[टकराव की तपिश में मध्य पूर्वः शक्ति, प्रतिरोध और अनिश्चित भविष्य]

मध्य पूर्व अचानक संघर्ष की भयंकर आग में झुलस रहा है। 6 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 'पूर्ण और बिना शर्त आत्मसमर्पण' की मांग की – कोई सौदा नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, सिर्फ पूरी तरह जीत। यह अल्टीमेटम युद्ध के सातवें दिन आया, जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हजारों लक्षित हमले किए। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि केवल आत्मसमर्पण के बाद ही ईरान में नया 'महान और स्वीकार्य नेता' चुना जाएगा और देश का पुनर्निर्माण होगा। इस मांग ने कूटनीतिक रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया है। वैश्विक मीडिया इसे 'मैक्सिमलिस्ट वॉर ऐम्स' के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिससे साफ है कि यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रह सकता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज़तबा खामेनेई ने इसे केवल एक 'सपना' करार देते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे तनाव और भी गहरा गया है। खामेनेई के कड़े शब्दों ने अमेरिका के लिए सीधे चुनौती खड़ी कर दी। ईरान ने ट्रंप का अल्टीमेटम ठुकराते हुए कहा, 'हम अंत तक लड़ेंगे।' इसके तुरंत बाद, ईरानी मल्टी-वारहेड मिसाइलों ने इज़राइल और गल्फ क्षेत्रों को विनाश की आग में ढक दिया। 10 मार्च तक, युद्ध के 11वें दिन, 140 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जिनमें 8 की स्थिति गंभीर है। पेंटागन चुप्प है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इसे 'साइलेंट किलर' मोड कहते हैं। ईरान ने क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय किया, जिससे लेबनान में 10 लाख लोग विस्थापित हुए। यह संघर्ष अब एट्रिशन वार की ओर बढ़ रहा है, जहां कोई स्पष्ट विजेता दिखाई नहीं देता। ट्रंप का दावा कि ईरान की मिसाइल क्षमता 80% कम हो गई है, हकीकत से मेल नहीं खाता, क्योंकि जवाबी हमले लगातार जारी हैं। रूस के साथ ईरान की बातचीत अमेरिकी आर्थिक दबाव को और गहरा रही है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट की कगार पर खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 'मेजर ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी' घोषित किया। अब तक 1000 से अधिक नागरिक स्थल तबाह हो चुके हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल रही है, बेरूत से तेहरान तक बमबारी जारी है। तेल की कीमतें 91 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई हैं और होर्मुज स्ट्रेट में खतरे के कारण और बढ़ सकती हैं। जर्मन चांसलर ने चेतावनी दी कि बिना ठोस एग्जिट प्लान के युद्ध अनंत तक खिंच सकता है। चीन ने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका और इजराइल को चुनौती न दें, जबकि रूस का समर्थन ईरान को जारी है। ट्रंप बार-बार 'विजय नजदीक' बता रहे हैं, लेकिन मिसाइल हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया की निगाहें थम गई हैं, क्योंकि किसी भी क्षण परमाणु खतरे का भय मंडरा रहा है।

भारत की ऊर्जा व्यवस्था संकट के सबसे गंभीर मोड़ पर है। देश का लगभग 50-60% तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता है, जो किसी भी समय पूरी तरह बंद हो सकता है और आपूर्ति ठप्प कर सकता है। पेट्रोल और डीजल 200 रुपये पार कर सकते हैं, जबकि एलपीजी की कमी घरेलू अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल रही है। हवाई यात्रा ठप हो गई, फ्लाइट्स 14 घंटे तक फंसीं और लाखों लोग प्रभावित हुए। फरवरी 2026 में आयातित तेल की मात्रा देश की कुल जरूरत का 53% थी, और अब वैकल्पिक स्रोतों की ओर नजरें गड़ाई गई हैं–रूस, अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका ही संभावित विकल्प बन रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दबाव और शांति के बीच संतुलन साधना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बैकचैनल्स के जरिए शांति के संकेत भेजे जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटम से पीछे हटना लगभग असंभव है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना रिजीम चेंज के कोई 'जादुई जीत' संभव नहीं। ईरान ने सरेंडर नहीं किया; उसका नेतृत्व और भी रेडिकल हो गया है। अमेरिकी बलों ने अब तक 5000 से अधिक टारगेट्स हिट किए, लेकिन ईरानी मिसाइलें लगातार जारी हैं। पेंटागन की चुप्पी वैश्विक स्तर पर सवाल खड़े कर रही है और यह अल्टीमेटम युद्ध को लंबा खींच सकता है, जिससे आर्थिक भार अमेरिका पर भारी पड़ेगा।

ईरान पूरी तरह अमेरिका को थकाने और दबाव में रखने की रणनीति पर केंद्रित है। होर्मुज स्ट्रेट और प्रमुख तेल पाइपलाइंस को निशाना बनाकर उसने वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ा दिया है। क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के लिए विद्रोही समूहों को सक्रिय करना उसकी रणनीति का हिस्सा बन गया है। युद्ध का कोई सुरक्षित ऑफ-रैंप न होने के कारण यह दावा कि यह जल्द खत्म होगा पूरी तरह खोखला लगता है। संघर्ष का प्रभाव अब खेलों और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों तक पहुँच गया है–भारतीय महिला फुटबॉल टीम के वीजा अटक गए, जबकि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हफ्तों तक फंसे रहे, कुछ खिलाड़ी कमर्शियल फ्लाइट्स से 9-10 दिन बाद घर लौट पाए, जिससे खेल जगत गहरे संकट में है।

डिप्लोमेसी अब सबसे अहम जरूरत बन गई है। रूस और ईरान की बातचीत जारी है, जबकि चीन की चेतावनी स्पष्ट और सख्त है। ट्रंप बैकचैनल्स के माध्यम से शांति के संकेत दे रहे हैं, लेकिन 'सरेंडर या डाई' अल्टीमेटम इसे रोक रहा है। ईरान न्यूक्लियर रिफाइनमेंट तेज कर सकता है, जो वैश्विक स्तर पर बड़ा खतरा पैदा करता है। अब दुनिया के नेताओं को तुरंत मध्यस्थता करनी होगी, वरना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहरा जाएगा। यह अल्टीमेटम इतिहास में दर्ज होगा–या तो अमेरिकी 'विजय' के रूप में, या गंभीर भूल के रूप में।

भविष्य की अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को गहरी चिंता में डाल दिया है। यदि ईरान पीछे नहीं हटता, तो यह संघर्ष लंबे एट्रिशन युद्ध में बदल सकता है–जहाँ मौतों की संख्या बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप को अपना अल्टीमेटम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, और घोषित 'विक्ट्री' केवल राजनीतिक बयान भर रह जाएगी। दूसरी ओर, ईरान अपने सहयोगियों के साथ अंत तक लड़ने का संकेत दे चुका है। भारत जैसे देश तटस्थ रहते हुए कूटनीति के रास्ते को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यह अल्टीमेटम शांति की संभावनाओं को कठिन परीक्षा में डाल रहा है। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि ट्रंप की दिखावटी ताकत भारी पड़ेगी या ईरान की दृढ़ता पूरी दुनिया को एक नए संकट के दौर में धकेल देगी।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

खाड़ी युद्ध व घरेलू राजनीति

पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल व अमेरिका युद्ध के चलते पूरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो संकट गहराता जा रहा है उससे अब भारत भी अछूता नहीं रहा है और देश ने ईंधन गैस के मोर्चे पर सतर्कता दिखानी शुरू कर दी है। इस सन्दर्भ में केन्द्र की मोदी सरकार ने आवश्यक उपभोक्ता सामग्री अधिनियम लागू कर दिया है जिसके चलते किसी भी जरूरी सामान की जमाखोरी या जखीरेबाजी नहीं की जा सकती। ऐसा करना इस कानून के तहत दंडनीय अपराध होता है। सरकार ने दो दिन पहले ही गैस ईंधन की किल्लत को देखते हुए इसकी कीमत में थोड़ा इजाफा भी किया था। इससे समझा जा सकता है कि दुनिया के किसी भी कोने में छिड़े युद्ध के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसकी मूल वजह यह है कि विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक- दूसरे से जुड़ने के बाद परस्पर निर्भरता के दौर में पहुंच चुकी हैं। यह परिवर्तन 1990 में विश्व व्यापार संगठन के मूर्त रूप में होने के बाद आया है। दुनिया के अधिसंख्य देश इस संगठन के सदस्य बन चुके हैं परन्तु अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के पुनः राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी नीतियों से यह संगठन लगातार अप्रासंगिक होता नजर आ रहा है क्योंकि ट्रम्प ने द्विपक्षीय आधार पर विभिन्न देशों के साथ आपसी कारोबारी समझौते की झड़ी लगा रखी है जिसकी वजह से हर देश को अपने कारोबारी राष्ट्रीय हितों को साधने की फिक्र हो गई है। मगर ट्रम्प ने अमेरिका को पुनः महान बनाने का जो राजनीतिक नारा दे रखा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में स्थापित वह व्यवस्था लड़खड़ा रही है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ हुआ था। इसके अनुसार दुनिया का हर छोटा- बड़ा देश एक-दूसरे की भौगोलिक संप्रभुता का सम्मान करेगा और अपनी ताकत के बूते पर किसी भी कमजोर देश की राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं करेगा लेकिन हमने देखा है कि 1945 के बाद से भी दुनिया के विभिन्न देशों में युद्ध हुए हैं और संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित मानकों का हनन हुआ है। हैरत करने वाली बात यह है कि कमोबेश रूप से इन सभी युद्धों में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है परन्तु 1990 से पहले सोवियत संघ के विघटन से पूर्व विश्व में दो महाशक्तियों सोवियत संघ व अमेरिका के बीच शक्ति सन्तुलन इस प्रकार रहता था कि दोनों ही दुनिया में अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों को अपने खेमों में लाने के प्रयास करते रहते थे। 1990 के बाद पूरा विश्व एक पक्षीय या एकल ध्रुवीय होता चला गया। अतः आज पूरे विश्व में जो शक्ति सन्तुलन है वह स्वाभाविक रूप से अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। ऐसे माहौल में ईरान के साथ पश्चिम एशिया में जो इजराइल व अमेरिका मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं उससे पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता संकट में पड़ती नजर आ रही है जिसकी चपेट में अधिसंख्य खाड़ी व अरब देश आ चुके हैं क्योंकि लगभग इन सभी देशों में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बहुत प्रभावी मानी जाती है। इसका कारण इन देशों की अपनी घरेलू राजनीतिक व शासकीय मजबूरियां मानी जाती हैं। इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पैट्रोलियम तेल के उत्पादन पर टिकी हुई है अतः ईरान-इजराइल युद्ध की चपेट में इन देशों के आ जाने के बाद सबसे बुरा असर पैट्रोलियम तेल की सप्लाई पर ही होना था। भारत चुंकि अपनी तेल व गैस ऊर्जा की आवश्यकताओं की खपत 85 प्रतिशत आयात से ही करता है अतः इस मोर्चे पर इसे सतर्कता बरतनी ही थी। इस वातावरण में हमें देश की राजनीति की परख करनी होगी समझना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र भारत को संसद से लेकर सड़क तक किस प्रकार के विमर्श के भीतर अपने राष्ट्रीय हितों को साधना चाहिए। फिलहाल संसद का सत्र चल रहा है और देश की विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशियाई युद्ध को लेकर व्यापक बहस व चर्चा कराई जाये।

लोकतन्त्र में ऐसी मांग को खारिज भी नहीं किया जा सकता है परन्तु असली सवाल यह है कि ऐसे माहौल में देश के सभी राजनीतिक दलों का कर्त्तव्य क्या बनता है। यह कर्त्तव्य सर्वप्रथम राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने का होता है। हम मानते हैं कि भारत में जितने भी राजनैतिक दल हैं वे सभी राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित हैं, बेशक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं परन्तु सभी भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहते हुए सामाजिक व राष्ट्रीय उत्थान के पक्षधर होते हैं।

अमेरिका ईरान युद्ध का असर भारत और गुजरात की ऊर्जा व्यवस्था पर

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का प्रभाव अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा है बल्कि इसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण भारत में तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। युद्ध के कारण होर्मुज जलमार्ग पर टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है जिससे भारत को मिलने वाली गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा बाधित हो गया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है और इसी कारण अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का सीधा प्रभाव देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है।

हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमत 118 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी हालांकि मंगलवार को इसमें कुछ गिरावट आई और कीमत लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर हुई। इसके बावजूद ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। भारत प्रतिदिन लगभग 19.1 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की खपत करता है और इस जरूरत का लगभग आधा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। युद्ध के कारण मध्य पूर्व से आने वाली लगभग 6 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है जिससे ऊर्जा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है।

स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाए हैं। सरकार ने गैस आवंटन की नई प्राथमिकताएं तय की हैं ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। एलपीजी सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इनकी मांग को पूरी तरह पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इसके विपरीत कमर्शियल उपयोगकर्ताओं को उनकी मांग का लगभग अस्सी प्रतिशत और उर्वरक उद्योगों को लगभग सत्तर प्रतिशत गैस आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर यह वितरण तय किया जाएगा। गैस आपूर्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी गेल को दी गई है ताकि उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हाल ही में कुछ स्थानों पर कमर्शियल सिलेंडरों की कमी को लेकर चिंताएं सामने आई थीं लेकिन अब आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देश की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने उत्पादन में लगभग दस प्रतिशत की वृद्धि भी की है। इसके साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं।

इस वैश्विक संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों पर पड़ा है जहां बड़ी संख्या में उद्योग गैस पर निर्भर हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से राज्य में कई उद्योगों को उत्पादन कम करना पड़ा है। गुजरात में गैस आपूर्ति में रुकावट के कारण छोटे दुकानों से लेकर बड़े होटलों और उद्योगों तक सभी प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर स्थिति लगभग लॉकडाउन जैसी हो गई है क्योंकि गैस की उपलब्धता कम होने से व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ा है।

सुरेंद्रनगर जिले में सिरेमिक उद्योग को इस संकट से बड़ा झटका लगा है। धानगढ़ क्षेत्र में लगभग सात सौ से अधिक कारखाने गैस पर निर्भर हैं और गैस आपूर्ति में पचास प्रतिशत तक कमी आने से उत्पादन लगभग ठप हो गया है। इससे करीब पचास हजार कारीगरों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। इसी तरह सूरत जिले में भी गैस की कमी के कारण कई होटलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। पलसाना हाईवे पर कुछ होटलों पर ताले लग गए हैं क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता खत्म हो गई थी। नवसारी जिले में भी पिछले तीन दिनों से कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री बंद रहने की खबरें सामने आई हैं।

गैस संकट के डर से घरेलू उपभोक्ताओं में भी चिंता बढ़ गई है। कई लोगों ने अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी है जिसके कारण एलपीजी सिलेंडर की मांग में लगभग बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुजरात में लगभग तिरासी लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता और छत्तीस लाख पीएनजी उपभोक्ता हैं। राज्य में कुल मिलाकर करोड़ों लोग गैस पर निर्भर हैं इसलिए ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट का असर सीधे आम जीवन पर पड़ता है। गुजरात में कुल 1042 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनमें से लगभग 488 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य में हर दिन लगभग 55 लाख किलो एलपीजी की मांग रहती है और वर्षभर में इसकी मांग करीब 200 करोड़ किलो तक पहुंच जाती है।

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए ईएसएमए कानून लागू किया है। इसका उद्देश्य गैस की जमाखोरी रोकना और आपूर्ति को नियमित बनाए रखना है। मेहसाणा और पंचमहल जैसे जिलों में पाइपलाइन गैस उपलब्ध होने से घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों के लिए कई स्थानों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दाहोद और पंचमहल जिलों में नए कोटे में कटौती के कारण आने वाले समय में हालात और कठिन होने की आशंका जताई जा रही है।

दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के भविष्य को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है और उन्हें उम्मीद है कि यह जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि ईरान तेल आपूर्ति को बाधित करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक उनके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते।

युद्ध की संभावनाओं के बीच खाड़ी देशों में भी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। परमाणु आपदा की आशंका को देखते हुए बहरीन और अन्य देशों ने न्यूक्लियर इमरजेंसी में उपयोग होने वाली दवाओं की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी से प्रशियन ब्लू कैप्सूल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को लेकर संपर्क किया गया है। इस दवा का उपयोग परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा की स्थिति में शरीर में प्रवेश कर चुके रेडियोएक्टिव तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। कंपनी से एक करोड़ कैप्सूल के उत्पादन की क्षमता और विभिन्न आयु वर्ग के लिए आवश्यक खुराक के बारे में जानकारी मांगी गई है।

प्रशियन ब्लू कैप्सूल डीआरडीओ की तकनीक पर आधारित है और इसे भारत में दो वर्ष पहले व्यावसायिक रूप से तैयार करना शुरू किया गया था। यह दवा शरीर में मौजूद रेडियोएक्टिव सीजियम और थैलियम जैसे तत्वों को बांधकर उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपात स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण दवाओं की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट की भी मांग बढ़ रही है जो परमाणु विकिरण से थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है।

इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध और संघर्ष केवल युद्धरत देशों तक सीमित नहीं रहते बल्कि उनका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति और आम जनजीवन पर पड़ता है। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठाकर घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की है लेकिन यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले समय में भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोतों और आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,** E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

मुस्लिम युवती ने हिन्दू रीति से मंदिर में रचाई शादी

अग्नि को साक्षी मानकर प्रेमी जोड़े बने पतिपत्नी

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र में प्रेम विवाह का एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी हिन्दू युवक से शादी कर ली। विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से मंदिर में संपन्न हुआ। शादी के बाद युवती ने हिन्दू धर्म अपनाते हुए अपना नाम भी बदल लिया। कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव की रहने वाली आईमन अहमद का गांव के ही युवक शिवम के साथ करीब पांच वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को विवाह का रूप देने का निर्णय लिया। परिवार और समाज की आशंकाओं के बीच दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ऐहार स्थित बाल्हेश्वर मंदिर पहुंचे। जहां विधि-विधान से हिन्दू परंपरा के अनुसार विवाह कराया गया। मंदिर में पुरोहित की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लिए। अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली। विवाह के बाद आईमन ने हिन्दू धर्म अपनाते हुए अपना नया नाम कृतिका रख लिया। शादी के बाद नवविवाहित दंपत्ति शिवम और कृतिका ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता आपसी विश्वास और प्रेम पर आधारित है। दोनों ने साथ मिलकर जीवन बिताने का निर्णय लिया है।

बाइक-साइकिल की टक्कर में बुजुर्ग किसान समेत दो घायल

लालगंज (रायबरेली)। उन्नाव हाईवे पर बुधवार को बाइक और साइकिल की आमने सामने टक्कर में बुजुर्ग किसान समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।शीतलाबख्श खेड़ा गांव निवासी बुजुर्ग किसान श्रीअवतार साइकिल से घर लौट रहे थे। तभी मदुरी गांव निवासी बाइक सवार राजकिशोर कुशवाहा ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार राज किशोर हेलमेट नहीं पहना था।

लखनऊ- हरदोई रोड पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत, सहेली की हालत नाजुक

लखनऊ-हरदोई रोड पर स्कूटी सवार युवती की मौत।

विपरीत दिशा में जा रही स्कूटी को अज्ञात बाइक ने टक्कर मारी।

मलिहाबाद। माल के अहमदपुर गांव निवासी 34 वर्षीय स्कूटी सवार युवती की मंगलवार रात रहीमाबाद स्थित हरदोई-लखनऊ रोड पर सड़क हादसे में मौत हो गई। साथ बैठी उनकी सहेली को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, अहमदपुर निवासी 34 वर्षीय पारुल अपनी सहेली सावित्री के साथ हरदोई के संडीला में नमकीन फैक्ट्री में नौकरी करती थी। मंगलवार देर रात वह संडीला से सहेली को लेकर रहीमाबाद के सेरनगर जा रही थी। वह लखनऊ-हरदोई रोड पर विपरीत दिशा में स्कूटी चला रही थी। हाइवे ढाबा के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सहेलियां छिटककर सड़क पर जा गिरी। घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने पारुल को मृत घोषित कर दिया। सावित्री की हालत नाजुक है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि सीसी फुटेज की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है। परिवार ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है।

रोड निर्माण में अनियमितताओं की भरमार ठेकेदार पर लगे गंभीर आरोप

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजना में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कृष्णा कॉलोनी कल्याण समिति ने एक शिकायती पत्र जारी किया है। जिसमें कॉलोनी के निवासियों ने ठेकेदार पर मानकों की अनदेखी करने और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। इस मुद्दे ने स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है, क्योंकि इससे कॉलोनी के सैकड़ों निवासियों की दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। कृष्णा कॉलोनी, जो आईआईएम रोड, रायपुर इलाके में स्थित है, लखनऊ के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है। यहां एलडीए द्वारा अविनाश सिंह के मकान से मुनेंद्र सिंह के मकान तक सीसी (कंक्रीट) रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। यह परियोजना कॉलोनी की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन अब इसमें गंभीर खामियां सामने आ रही हैं।

कल्याण समिति के अध्यक्ष पी.के. राय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ठेकेदार नक्शे के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। पत्र के अनुसार, जल निकासी की नालियां गलत दिशा में बनाई जा रही हैं, जिससे बरसात के मौसम में कॉलोनी के घरों में पानी भरने की संभावना बढ़ गई है। इससे न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जो सड़क की गुणवत्ता और स्थायित्व पर सवाल खड़े करता है।

पत्र में लिखा गया है, 'उक्त कार्य में नाली खोदने की जल निकासी की दिशा विपरीत दिशा में बनाई जा रही है, जिसकी वजह से कॉलोनी वासियों के घरों में पानी भरने की संभावना है। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है।' समिति ने एलडीए के निदेशक से अनुरोध किया है कि वे स्वयं या तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के माध्यम से जांच कराएं और मानकों के अनुसार कार्य पूरा करवाएं।

इस शिकायत के पीछे कॉलोनी के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, आईआईएम रोड क्षेत्र में विकास कार्यों में अक्सर ऐसी अनियमितताएं देखी जाती हैं, जहां ठेकेदार लाभ कमाने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता करते हैं। एक स्थानीय निवासी, जो नाम न छापने की शर्त पर बात की, ने बताया, 'हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अब यह रोड बनने से पहले ही समस्या पैदा कर रहा है।

अगर जल निकासी सही नहीं हुई, तो मानसून में पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। 'कृष्णा कॉलोनी कल्याण समिति एक पंजीकृत संगठन है, और यह कॉलोनी के कल्याण और विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करती है। एलडीए के अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क करने पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली, यह घटना लखनऊ में विकास परियोजनाओं की निगरानी की कमी को उजागर करती है, जहां अक्सर स्थानीय समितियां ही आवाज उठाती हैं।

ऐसे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। एक 'जल निकासी की दिशा गलत होना एक बड़ी लापरवाही है। इससे न केवल बाढ़ का खतरा बढ़ता है, बल्कि सड़क की उम्र भी कम हो जाती है। एलडीए को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। कॉलोनी के निवासी अब इस शिकायत के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यदि जांच में देरी हुई, तो समिति आगे की कार्रवाई, जैसे धरना या कोर्ट जाने पर विचार कर सकती है। यह घटना लखनऊ के अन्य कॉलोनियों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां विकास कार्यों में निवासियों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।

चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में मनाई गई चंद्रभानु गुप्त की 46वीं पुण्यतिथि

स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और जननायक चंद्रभानु गुप्त जी की 46 वीं पुण्यतिथि पर चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेंद्र कुमार सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। डॉ योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 1995 में श्रद्धेय बाबू भगवती सिंह ने चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसमें लगभग 100 से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी पूरे महाविद्यालय में कार्यरत हैं एवं लगभग 1700 से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया ने बताया कि महाविद्यालय में बीएससी (ऑनर्स) कृषि एमएससी (कृषि)बीकॉम तथा बी बी ए की शिक्षा दी जाती है महाविद्यालय में उत्तर प्रदेशसहित अन्य प्रदेशों के छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चंद्रभानु गुप्त जी उन विरले नेताओं में थे जिन्होंने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का साधन माना।

उनका सादगीपूर्ण जीवन, दृढ़ इच्छाशक्ति और गरीब-वंचित वर्ग के उत्थान के प्रति समर्पण उन्हें एक आदर्श जननेता के रूप में स्थापित करता है। उत्तर प्रदेश के विकास, शिक्षा के विस्तार और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे। उनकी पुण्यतिथि पर महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ सुधीर कुमार रघुवंशी एवं धनेंद्र कुमार सिंह सहित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों कर्मचारियो ने गुप्त जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर। चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ हुआ जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। प्रथम दिन इकाइयों के संयोजकों द्वारा छात्र-छात्राओं को सेवा योजना के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। पिडीलाइट कंपनी की संयोजिका राखी निगम द्वारा छात्र-छात्राओं को आर्ट एंड क्राफ्ट पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम दिन सेवा योजना इकाईयों द्वारा गोद लिए गए गांवों में वृक्षारोपण किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत एवं राष्ट्रगान गाकर शिविर का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी धनेंद्र कुमार सिंह, डॉ आशुतोष श्रीवास्तव डॉ दीप्ति श्रीवास्तव एवं डॉ सुधीर कुमार सिंह रघुवंशी, डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ के डी सिंह, उरूज आलम सिद्दीकी, राहुल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी शिव मंगल चौरसिया सहित सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को सड़क सुरक्षा पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा तथा जनमानस को जागरूक करने के लिए विशाल रैली निकाली जाएगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं 30 और 31 मार्च को

लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी (नियमित) के लिए बुधवार को अनुसंधान प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि घोषित कर दी। प्रवेश परीक्षा 30 और 31 मार्च को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी ने दो या अधिक विषयों में आवेदन किया है और उनकी परीक्षाएं एक ही दिन व सत्र में निर्धारित हैं, तो वे 16 मार्च तक ईमेल luadmissionswz@gmail.com के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे इस संभावित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करें और किसी भी अद्यतन सूचना के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एवं ईमेल संचार पर ध्यान दें। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने पीएचडी में प्रवेश के लिए आठ मार्च तक आवेदन का मौका दिया था।

रसोई गैस की किल्लत, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

● बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, उपभोक्ता परेशान; होटल-ढाबा कारोबार भी प्रभावित

स्वतंत्र प्रभात

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे और आसपास के गांवों में रसोई गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बुधवार को बाईपास स्थित एक गैस एजेंसी पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। यहां गैस बुकिंग और सिलेंडर वितरण को लेकर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों का कहना है कि एक सप्ताह पहले कराई गई बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।

पूरे गुरदी मजरे पौशाला मोहल्ला निवासी उपभोक्ता राजू ने बताया कि कई दिन पहले गैस बुकिंग कराई थी, लेकिन अब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। इससे घर की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

गैस की कमी का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। कामर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से ढाबा और होटल संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग मजबूरी में कोयले की भट्ठी से काम चला रहे हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े राम सिंह चौहान ने बताया कि हाल ही में गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं और अब आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। इससे कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है।

नो स्मोकिंग डे के अवसर पर गोष्ठी एवं हस्ताक्षर अभियान का आयोजन संपन्न

स्वतंत्र प्रभात

रायबरेली:- मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 नवीन चंद्रा के निर्देशन में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 'नो स्मोकिंग डे' के अवसर पर गोष्ठी एवं हस्ताक्षर अभियान, का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली में किया गया। कार्यशाला में प्रतिभागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डा0 अरुण कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा जनपद में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। कार्यशाला में कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू धूम्रपान निषेध परिसर के बारे में बताया गया।

पूनम यादव, जिला परामर्शदाता, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि जन-मानस में तम्बाव तम्बाकू का सेवन बहुत अधिक मात्रा में पुरुषों के साथ महिलाओं द्वारा भी किया जा रहा है। जिसके परिणाम बहुत ही गम्भीर है, तम्बाकू का धुआँ रहित या धुएं के साथ दोनों तरह का उपयोग समाज के लिए हानिकारक है। जिनमें मुख्यतः युवाओं को तम्बाकू के कुप्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें धुम्रपान न करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की मुख्य भूमिका है। साथ ही युवाओं को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों एवं हानियों के प्रति जागरूकता लाये जाने के साथ-साथ उनके आस-पास तम्बाकू प्रयोग कर रहे लोगों को तम्बाकू सेवन छोड़ने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की जिम्मेदारी देकर उन्हें इस तरह के तम्बाकू सेवन से बचाया जा सकता है।

कार्यशाला में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके स्वयं के परिसर को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाये रखने के साथ-साथ मरीजो को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 अरविन्द कुमार, डॉ0 राकेश कुमार, डॉ0 अम्बिका प्रसाद, जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी डी0एस0 अस्थाना, डी0पी0एम0 राकेश कुमार सहित कार्यालय के समस्त अधिकारी एंव कर्मचारी उपस्थित रहें।

राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने की जनसुनवाई, कई मामलों का मौके पर निस्तारण

● निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर

स्वतंत्र प्रभात

गोण्डा। उ.प्र. राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही का बुधवार को जनपद में आगमन हुआ। उन्होंने सर्किट हाउस में महिला संबंधी जनसुनवाई की और पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान कुल 17 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 09 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि शेष 08 प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता है।

इसके बाद गांधी पार्क स्थित टाउनहॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकती हैं।कार्यक्रम के उपरांत ऋतु शाही ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, दर्जीकुंआ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की खिड़की का शीशा टूटा हुआ पाया गया, जिस पर उन्होंने तत्काल उसे ठीक कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय उपाध्याय, महिला थाना प्रभारी अनीता यादव, संरक्षण अधिकारी चन्द्रमोहन वर्मा, सेंटर मैनेजर चेतना सिंह, प्रियंका सिंह, सिद्धनाथ पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मऊ गांव में फाग के सुरों के साथ गूंजा होली मिलन समारोहः 'शिवाय सेवा समिति' ने सहेजी 14 वर्षों की गौरवशाली परंपरा

● .....पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर थिरके ग्रामीण, फाग महोत्सव में लोक संस्कृति और आपसी भाईचारे का अनूठा संगम।

स्वतंत्र प्रभात

विनीत कुमार मिश्रा(जिला संवाददाता)

लखनऊ (मोहनलालगंज): राजधानी के मोहनलालगंज तहसील स्थित मऊ गांव में मंगलवार को भक्ति, संस्कृति और उल्लास का अद्भुत मेल देखने को मिला।14 वें वार्षिक फाग महोत्सव का आयोजन रंजीत यादव उर्फ गुड्डू की अगुवाई में होली मिलन समारोह ने पूरी ग्राम सभा को फागुन के रंगों से सराबोर कर दिया। पिछले 14 वर्षों से निरंतर चली आ रही इस धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ने इस बार भी अपनी भव्यता से क्षेत्रीय लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण कलाकारों ने पारंपरिक लोक विधाओं के जरिए न केवल समां बांधा, बल्कि आधुनिकता के दौर में लुप्त होती ग्रामीण जड़ों को फिर से जीवंत करने का संदेश भी दिया।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षणः रंजीत यादव 'गुड्डू' की अनूठी पहल.....

महोत्सव के मुख्य आयोजक और शिवाय सेवा समिति के संस्थापक/सचिव रंजीत यादव उर्फ 'गुड्डू' ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय लोक संस्कृति और फाग जैसी विधाएं हमारे ग्रामीण जीवन की आत्मा हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह महोत्सव केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और गौरवशाली विरासत से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। रंजीत यादव के अनुसार, ऐसे कार्यक्रमों से आपसी कटुता मिटती है और समाज में भाईचारे की भावना सुदृढ़ होती है। इसी उद्देश्य के साथ समिति हर वर्ष होली के उपलक्ष्य में इस भव्य मिलन समारोह का खाका तैयार करती है।

लोक गायकों की जुगलबंदी और अतिथियों का सत्कार.....

इस वर्ष फाग महोत्सव में धनुवासांड, राजाखेड़ा और मऊ की प्रसिद्ध मंडलियों ने अपनी गायकी से समां बांध दिया। कार्यक्रम में मास्टर सुंदर लाल, त्रिलोकी यादव, नीलकंठ और राजाखेड़ा से आए श्रीराम व इंदल जैसे मंझे हुए कलाकारों ने जब ढोलक और मजीरों की थाप पर फाग के गीत छेड़े, तो उपस्थित जनसमूह झूम उठा। शिवाय सेवा समिति के अध्यक्ष आशीष चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष राहुल मिश्र, अखिलेश शुक्ल, पांशुल तिवारी, पंकज गुप्ता और गिरिजा गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की और इस सांस्कृतिक यज्ञ को अगले वर्ष और भी भव्य रूप देने का संकल्प लिया।

कचरे से रोजगार का 'रामपुर मॉडल', खराब एंबुलेंस बनीं मोबाइल शॉप; रेहड़ी-पटरी संचालकों की बदली दुनिया

● पुरानी एंबुलेंस को मोबाइल दुकानों में बदला गया।

गरीब रेहड़ी-पटरी संचालकों को मिला स्थायी रोजगार।

रामपुर में 'जीरो वेस्ट' और 'वेस्ट टू वेल्थ' मॉडल।

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में नवाचार और विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से संसाधन) के विजन को मिशन मोड में अपनाते हुए रामपुर जिला प्रशासन ने एक बेहद अनूठी और सराहनीय पहल शुरू की है। जिले में 'जीरो वेस्ट मॉडल' को धरातल पर उतारते हुए प्रशासन ने कबाड़ हो चुकी और निष्क्रिय एंबुलेंस को नया जीवन दिया है। इन अनुपयोगी वाहनों को आधुनिक मोबाइल दुकानों (वैनशॉप) में बदलकर गरीब रेहड़ी-पटरी संचालकों को रोजगार के लिए सौंपा गया है, जो प्रदेश में अपनी तरह का पहला मॉडल बनकर उभर रहा है।

कचरे को बनाया संसाधन, एंबुलेंस बनी वैनशॉप

रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कचरा प्रबंधन को लेकर अत्यंत गंभीर हैं और उनका संदेश है कि कचरे को समस्या नहीं, बल्कि अवसर समझा जाए। इसी क्रम में प्रशासन ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में वर्षों से धूल फांक रही 8 पुरानी और निष्क्रिय एंबुलेंस को चिन्हित किया। 'जीरो वेस्ट' पहल के तहत इन निष्प्रयोज्य वाहनों को कबाड़ में बेचने के बजाय मॉडिफाई कर आकर्षक मोबाइल वैनशॉप का रूप दिया गया है। इन वैनों को अब रेहड़ी-पटरी संचालकों को आवंटित कर उन्हें स्थायी आजीविका का साधन उपलब्ध कराया गया है।

जाम से मुक्ति और सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन

नगर क्षेत्र में लंबे समय से बेतरतीब ठेलों और अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता था, जिससे छोटे कारोबारियों को भी बार-बार हटाए जाने के डर से रोजगार का संकट रहता था। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए फोटो चुंगी के समीप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत एक अत्याधुनिक वेंडिंग जोन विकसित किया गया है। यहाँ इन मॉडिफाई की गई 8 वैनशॉप को स्थापित किया गया है, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था सुधरी है, बल्कि रेहड़ी-पटरी संचालकों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक व्यावसायिक स्थान प्राप्त हुआ है।

एक ही छत के नीचे मिनी बाजार का अनुभव

इस वेंडिंग जोन के विकसित होने से आम जनता को भी बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। अब स्थानीय लोगों को कपड़े, खाने-पीने की वस्तुएं, फास्ट फूड और बच्चों के खिलौने जैसे दैनिक उपयोग के सामान एक ही स्थान पर मिलेंगे। जिलाधिकारी ने स्वयं इन दुकानों का निरीक्षण कर विक्रेताओं का उत्साहवर्धन किया। प्रशासन की योजना है कि शहर के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के वेंडिंग जोन विकसित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को सशक्त बनाया जा सके और रामपुर को एक सुव्यवस्थित डिजिटल और आधुनिक शहर के रूप में निखारा जा सके।

संक्षिप्त खबरें

इतिहास राष्ट्र की सामूहिक

स्मृति है, इसे प्रमाणों तथा शोध के आधार पर समझना जरूरी- प्रोफेसर इंदू भूषण द्विवेदी

इतिहास विज्ञान आधारित गोष्ठी संपन्न

मीरजापुर। भारतीय इतिहास संकलन समिति की जिला इकाई के तत्वावधान में जीडी बिनानी पीजी कॉलेज में बुधवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने और साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लेखन की आवश्यकता पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर विषय पर अपने विचार रखे। गोष्ठी का विषय इतिहास विज्ञान आधारित अंत्याधुनिक दृष्टि रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समिति के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर इंदू भूषण द्विवेदी ने कहा कि इतिहास राष्ट्र की सामूहिक स्मृति है और इसे प्रमाणों तथा शोध के आधार पर समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि इतिहास को साक्ष्यों की कसौटी पर नहीं परखा गया तो आने वाली पीढ़ियों को वास्तविक ऐतिहासिक दृष्टि नहीं मिल सकेगी। भारतीय इतिहास संकलन समिति का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों का संकलन कर उन्हें शोध के लिए उपलब्ध कराना है।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जीडी बिनानी पीजी कॉलेज के प्राचार्य एवं काशी प्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक सिंह ने कहा कि इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि प्रमाणों पर आधारित ज्ञान की विधा है। इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेखीय दस्तावेज, शिलालेख, साहित्यिक स्रोत और वैज्ञानिक अनुसंधान

की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन स्रोतों के समन्वित अध्ययन से ही किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक चेतना को सही दिशा मिलती है।समिति की प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर अनुराधा सिंह ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। इतिहास के अध्ययन को केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। समाज, संस्कृति, लोकजीवन और ज्ञान परंपरा भी इतिहास की महत्वपूर्ण धारा हैं। उन्होंने नई पीढ़ी में इतिहास के प्रति जिज्ञासा और शोध की भावना विकसित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ शशिधर शुक्ला ने किया ।इस अवसर पर डॉ ध्रुव जी पांडे, डॉ ऋषभ कुमार और श्याम मोहन उपाध्याय,प्रो राजेश पाण्डेय ने भी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में इतिहास के क्षेत्र में शोध, दस्तावेजीकरण और स्थानीय ऐतिहासिक स्रोतों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट में खाना बनाने की मुश्किल, LPG गैस की कमी से कैंटीन ने मेन कोर्स बंद

नई दिल्ली। ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के युद्ध के कारण एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी का असर दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों की कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर न होने की वजह से कुछ समय के लिए मेन कोर्स का खाना देना बंद कर दिया है। कैंटीन प्रबंधन की तरफ से जारी एक नोटिस में बताया गया कि एलपीजी की कमी की वजह से खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। कैंटीन प्रबंधन ने यह भी कहा कि गैस आपूर्ति दोबारा कब शुरू होगी, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जैसे ही गैस आपूर्ति उपलब्ध होगी, खाना बनना फिर से शुरू कर देंगे। हालांकि, अन्य रेडिमेड खाने-पीने चीजें उपलब्ध हैं।

पहले भी हो चुके थे डिपोर्ट, फिर दिल्ली में पकड़े गए दो बांग्लादेशी नागरिक; दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

● जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मोबाइल में प्रतिबंधित ऐप और छह बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि दोनों को पहले भी भारत से डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद वे दोबारा अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर दिल्ली में रह रहे थे।पुलिस के अनुसार 9 मार्च 2026 को फॉरेनर सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास सक्रिय हैं और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और लगातार सर्विलांस के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने शुरुआत में खुद को भारतीय नागरिक बताया, लेकिन उनके जवाबों में विरोधाभास और संदिग्ध व्यवहार के कारण पुलिस को उन पर शक हुआ।जांच के दौरान पुलिस ने उनके दस्तावेजों की जांच की, डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण किया और फोटो साक्ष्यों की पड़ताल की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों व्यक्ति बांग्लादेश के नागरिक हैं और बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों को पिछले वर्ष उत्तराखंड से अवैध रूप से भारत में रहने के कारण डिपोर्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वे दोबारा सीमा पार कर भारत आ गए और दिल्ली में अवैध गतिविधियों में शामिल हो गए।

दरअसल, हाल ही में फॉरेनर सेल ने तीन बांग्लादेशी महिलाओं को भी डिपोर्ट किया था, जो मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़े रैकेट में शामिल थीं। पूछताछ के दौरान उन महिलाओं ने खुलासा किया था कि 'विकास' नाम का एक बांग्लादेशी नागरिक उन्हें अवैध तरीके से भारत लाया था और दिल्ली में उनके लिए ग्राहकों का इंतजाम करता था। इसी खुलासे के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर निगरानी शुरू की। इसी दौरान पता चला कि वही व्यक्ति और उसकी कथित पत्नी जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास सक्रिय हैं।इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें एसआई श्यामबीर, एएसआई विजय, एएसआई राजेंद्र, महिला हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल दीपक बांगड़ शामिल थे।

यह टीम इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में और एसीपी राजीव कुमार की निगरानी में काम कर रही थी। टीम ने इलाके में स्टिंग ऑपरेशन भी किया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने संदिग्धों से अवैध गतिविधियों के लिए संपर्क किया। जैसे ही संदिग्धों ने सहमति जताई, पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया।तलाशी के दौरान उनके पास से दो स्मार्टफोन बरामद हुए, जिनमें प्रतिबंधित ढ्ढस्द्ब एप इंस्टॉल था। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की गैलरी से छह बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र भी मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। इन बरामदगी से यह भी पुष्टि हुई कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और यहां गलत गतिविधियों में शामिल थे।पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए एफआरआरओ के सामने पेश किया गया, जहां से उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय दिसो कुमार पाल उर्फ विकास और 27 वर्षीय रुमा बेगम के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के ढाका जिले के निवासी बताए गए हैं।

छात्रवृत्ति और टैबलेट की मांग को लेकर बलिया में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। जिले में छात्रवृत्ति और टैबलेट की मांग को लेकर बुधवार को हजारों छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को छात्रवृत्ति के भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह 'झुन्नू' ने कहा कि बलिया में पिछले दो-तीन वर्षों से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि छात्रवृत्ति आती भी है तो केवल करीब 10 प्रतिशत छात्रों को ही इसका लाभ मिलता है, जबकि 90 प्रतिशत छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार छात्रवृत्ति के लिए बजट पास करती है, तो हर पात्र छात्र को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए।

छात्र नेताओं ने सरकार द्वारा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि सरकार ने यह वादा किया है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि छात्रों को पढ़ाई में सुविधा मिल सके।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बलिया नगर विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भी अपील की कि वे जिले के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए पहल करें। छात्र नेता अविनाश सिंह नंदन ने कहा कि उनकी दो प्रमुख मांगें हैं—पहली, सभी पात्र छात्रों के खातों में पूरी छात्रवृत्ति भेजी जाए और दूसरी, सरकार द्वारा घोषित मोबाइल फोन या टैबलेट छात्रों को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र आंदोलन को और तेज करेंगे और अगला कदम 'छात्र कर्फ्यू' हो सकता है।

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 मार्च को, क्या है नया समय और स्थान?

नई दिल्ली। राजधानी में 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत को टाल दिया गया है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (डीएसएलएसए) ने 22 मार्च की नई तारीख तय की है। डीएसएलएसए के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 14 मार्च को हाई कोर्ट के तहत आने वाली सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग डे घोषित किया है। इसलिए, डीएसएलएसए के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस वी. कामेश्वर राव के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत को रीशेड्यूल करने का फैसला किया गया। नेशनल लोक अदालत अब 22 मार्च को तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी। इसमें तलाक के मामलों को छोड़कर, सिविल और क्रिमिनल मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

जल जीवन मिशन के तहत 1.90 करोड़ से बनी टंकी से ग्रामीणों को मिलने लगा स्वच्छ जल

● जल जीवन मिशन के तहत 1.90 करोड़ से बनी टंकी से ग्रामीणों को मिलने लगा स्वच्छ जल

भीखी सराय में हुआ जल अर्पण कार्यक्रम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

अयोध्या। जिले के बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत भीखी सराय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पानी की टंकी से अब ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिलना शुरू हो गया है। इस अवसर पर गांव में जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव में करीब एक करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है। इस योजना के तहत अब तक 321 ग्रामीणों को घर-घर पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा मिलने लगी है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए दूर-दूर तक भटकने की समस्या से राहत मिलेगी।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। उनके अनुपस्थित रहने पर ग्राम प्रधान ने फीता काटकर जल अर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ग्रामीणों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद गिरिना सिंह ने ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कई बार लोग नल खुला छोड़ देते हैं जिससे पानी बेकार बहता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य, पशु-पक्षी सभी के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमें जल को बचाकर रखना होगा। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान सहित इस योजना से जुड़े कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट मैनेजर उपेंद्र सिंह, सहायक अभियंता सिद्धार्थ शंकर पांडेय, अवर अभियंता कर्मवीर गौतम विक्रम पांडेय (पंप ऑपरेटर), अनंतराम, इंजीनियर कृष्णा, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने इस योजना को गांव के विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

नौकरी की तलाश अब खत्म-स्टूडेन्टस और जॉब ढूंढने वालो के लिए कम्पनियो के साथ

● सीधे इन्टरव्यू और जॉब के बेहतरीन अवसर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बस्ती एवं किसान डिग्री कालेज बस्ती के तत्वावधान में दिनांक- 18 मार्च 2026 दिन बुधवार को प्रातः 09 बजे से स्थान- शिव हर्ष किसान पी0जी0 कालेज-बस्ती में निःशुल्क एकदिवसीय वृहद् रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेला में देश की जानी-मानी 20 से भी अधिक प्रतिष्ठित कम्पनिया साथ ही स्थानीय नियोजक भी साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न पदो पर भर्ती करने हेतु आयेंगी। आने वाली कंपनियों मे प्रमुख रूप से टाटा मोटर्स लखनऊ, श्रीराम पिस्टन एवं रिंगस नोएडा, गाजियाबाद, बर्धमान टेक्सटाइल्स पंजाब, भारत शीट लिमिटेड गुजरात, नील मेटल हरियाणा, जे0बी0एम कम्पनी गुजरात, जमाटो गुड़गाव, एल.एन.टी. डस्की स्टालिन आदि कम्पनिया आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वालों के लिय टेक्निकल/मशीन आपरेटर/फ्रेसर पदों पर नॉन टेक्निकल के लिय- 8 से 10 व 12 पास पर भर्ती करेगीं। वही आई0डी0बी0आई, एच.डी.एफ.सी, एस.बी. आई.लाइफ इन्सुरेंस, ऐयु स्माल फाइनेंस, एल0आई0सी, आदि कम्पनिया बैकिंग क्षेत्र में स्नातक व परास्नातको के लिय विभिन्न पदो पर भर्ती करने हेतु आयेंगी।

बस्ती रोडवेज डिपो के भर्ती अधिकारीगण सविदा चालक के 50 पदों पर हैवी लाइसेन्स के साथ दो वर्ष का अनुभव काम से काम 8 पास आहर्ता वालो के लिय भर्ती करेगीं। पैराग्रीन प्रा0लि0 सिक्योरिटी गार्ड के लिए तथा अमेजोन, डिलिवरी व्याय के हेतु जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस (डी एल) होना चाहिए के लिए भर्ती करने हेतु आयेंगी। इस तरह कुल 5000 रिक्त पदो के साथ विभिन्न कंपनिया प्रतिभाग करेंगी। वेतनमान 6000.00 से 22000.00 तक रहेगा। इस रोजगार मेला में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 वी पास, हाईस्कुल, इण्टरमीडिएट, स्नातक ,आई0टी0आई0, डिप्लोमा कंप्यूटर दक्षता व अन्य तकनीकी गैर तकनीकी योग्यता धारक हो सकते है। इस रोजगार मेला में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी बायोडाटा व एक फोटो के साथ तिथि 18 मार्च 2026 दिन बुधवार समय सुबह-9 बजे से आयोजन स्थलः-शिव हर्ष किसान पी0जी0 कालेज-बस्ती मे निःशुल्क प्रतिभाग कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बस्ती (कटरा मुड़घाट रोड) पर किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है। यह जानकारीजिला सेवायोजन अधिकारीबस्ती ने दिया।

राजधानी की सड़कों पर दौड़े पिंक व्हील्स महिला दिवस पर फिटनेस और सशक्तिकरण का संदेश

● मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से निकली 'पिंक साइक्लोथॉन' रैली में 1000 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी, महिलाओं के स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली को मिला बढ़ावा।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लेजर स्किल्स काउंसिल (SPEFL-SC) ने फिट इंडिया मूवमेंट के सहयोग से 'संडेज़ ऑन साइकिल' के एक विशेष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम रविवार, 8 मार्च 2026 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। 'पिंक साइक्लोथॉन' पहल के इस तीसरे संस्करण ने महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए समाज के एक ख़ास वर्ग को आगे लाने का कार्य किया।सुबह की शुरुआत जबरदस्त ऊर्जा और फिटनेस के प्रति मिले-जुले जोश और जुनून के साथ हुई। मास फिटनेस सेशन में शामिल प्रतिभागियों ने जुम्बा, योग और रस्सी कूद जैसी गतिविधियों में भाग लिया। इस आयोजन की मुख्य साइकिल रैली को सुबह 7:45 बजे आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य पूरे शहर में फिटनेस और सक्रिय जीवन को बढ़ावा देना था। इस साइक्लोथॉन में सभी आयु वर्ग और लिंग के 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में प्रमुख फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और उन प्रसिद्ध महिला एथलीटों को सम्मानित किया गया जिन्होंने भारतीय खेलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों और खेल दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें श्री मयंक श्रीवास्तव उप महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण - खेलो इंडिया डिवीजन, सुश्री मंजुश्री दयानंद उप महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण), श्री तहसीन ज़ाहिद मुख्य कार्यकारी अधिकारी - SPEFL-SC, सुश्री नंदिनी अगासर (2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन स्वर्ण पदक विजेता,॰ द्मह्यद्धद्ब4 आशालता देवी (भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कप्तान), सुश्री गरिमा चौधरी ओलंपियन जूडोका सुश्री तनिष्का खत्री एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता तलवारबाज शामिल थे।

स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कई इन्फ्लुएंसर्स को भी सम्मानित किया गया, जिनमें डॉ. रीरी त्रिवेदी मानसिक स्वास्थ्य फिटनेस, सुश्री निधि निगम (पोषण), और टेलीविजन जगत की हस्तियां श्री तरुण खन्ना और सुश्री ऐश्वर्या राय शामिल थीं। साइक्लोथॉन के दौरान, 5 भाग्यशाली विजेताओं ने नई साइकिलें भी जीतीं। स्किल इंडिया, SPEFL-SC, NSDC और FICCI द्वारा समर्थित यह पहल, पिंक साइक्लोथॉन के उन व्यापक उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जिनका लक्ष्य प्रिवेंटिव हेल्थ (निवारक स्वास्थ्य) और महिला कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

राइड के बाद, गणमान्य व्यक्तियों ने मीडिया के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने देश भर में महिलाओं की दिनचर्या में खेल और फिटनेस को शामिल करने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। 'इस सफल कार्यक्रम के आयोजन में वेदांता का विशेष सहयोग रहा, जिसके कारण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सका।

दिल्ली विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

● शासन की असली परीक्षा बहस में नहीं, बल्कि ऐसी नीतियों में है जो आम नागरिक के जीवन में वास्तविक सुधार लाएँ श्री विजेन्द्र गुप्ता

● एसआरसीसी के पूर्व छात्र एवं दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 'माइन्ड्यूक्टर 14.0' में मुख्य भाषण दिया

● सार्वजनिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि ऐसी नीतियाँ बनाना है जो लोगों की सेवा करें विधानसभा अध्यक्ष

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली, बौद्धिक ईमानदारी और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का सशक्त संदेश देते हुए अपने पुराने शिक्षण संस्थान (अल्मा मेटर) में लौटे दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'माइन्ड्यूक्टर 14.0' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। छात्रों, प्राध्यापकों और युवा नेतृत्वकर्ताओं की एक उत्साहपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा किया तथा नेतृत्व, सुशासन, राष्ट्र-निर्माण और सार्वजनिक नीति के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए।अपने विचारोत्तेजक मुख्य भाषण में श्री गुप्ता ने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र का सार केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सार्थक और प्रभावी नीति-क्रियान्वयन तक पहुँचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न मत और असहमति स्वाभाविक हैं, किंतु शासन की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जाती है कि कानून और नीतियाँ आम नागरिक के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।श्री गुप्ता ने आगे कहा कि यह जिम्मेदारी विधायी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभाएँ और संसद ऐसे मंच हैं जहाँ सार्वजनिक मुद्दों पर गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ विचार-विमर्श किया जाता है तथा समाज के हित में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, 'एक विकसित भारत की पहचान उन संस्थानों से होती है जो ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हैं, तथा उन कानूनों से जो प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हैंएसआरसीसी की शैक्षणिक उत्कृष्टता को 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होती। वास्तविक विकास संस्थागत मजबूती, अवसरों के विस्तार और ऐसी संवाद संस्कृति से उत्पन्न होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि जब विभिन्न विचारों को सम्मान और शालीनता के साथ सुना और उन पर विमर्श किया जाता है, तो

सार्वजनिक नीतियाँ अधिक संतुलित और स्थायी बनती हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा, 'आपके विचार बौद्धिक ईमानदारी, नैतिक मूल्यों और व्यापक जनहित के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित होने चाहिए।' भारत के आर्थिक और प्रशासनिक भविष्य के निर्माता के रूप में छात्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी आज के युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने एसआरसीसी के प्रतिभाशाली और विचारशील छात्रों, भविष्य के अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और उद्यमियों को अपनी पेशेवर भूमिकाओं को सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया अपने संबोधन के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि युवाओं के विचार और प्रयास व्यापक राष्ट्रीय हित और समाज की सेवा के उद्देश्य से प्रेरित होंगे, तो एक ऐसे विकसित भारत का सपना साकार होगा जहाँ शासन उद्देश्यपूर्ण हो और कानून वास्तव में जनता की सेवा करें।

स्वतंत्र प्रभात
जो लिखेगा, वही टिकेगा, वही दिखेगा
स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अखबार, पत्रिका एवं ऑनलाइन चैनल में काम करने हेतु अनुभवी लोगों की आवश्यकता है।
जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरोचीफ, संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें।
अपना बायोडाटा भेजे : 9511151254
www.swatantraprabhat.com www.epaper.swatantraprabhat.com